संरक्षणवाद की दीवार बना रहे विकसित देश

नई दिल्ली में बृहस्पतिवार को माइंडमाइन समिट में अपने विचार व्यक्त करतीं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण।

■ नई दिल्ली।

भारत ने अमेरिका और आस्ट्रेलिया जैसे कुछ देशों द्वारा अपनी वीजा व्यवस्था को सख्त करने पर चिंता जताई। इसके साथ ही भारत ने सेवाओं के व्यापार को लागू करने को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) समर्थित वैश्विक ढांचे पर जोर दिया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को यहां कहा कि भारत ने डब्ल्यूटीओ को एक प्रस्ताव देकर सेवाओं में व्यापार सुविधा पर करार की मांग की है।

उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों का उदाहरण दिया जो कुशल पेशेवरों की आवाजाही के लिए अपनी वीजा व्यवस्था को कड़ा कर रहे हैं। सीतारमण ने कहा, 'अब विभिन्न देश सेवाओं के व्यापार के मामले में स्पष्ट तौर पर संरक्षणवाद की दीवार खड़ी कर रहे हैं।'

■ वीजा सख्ती पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने जताई चिंता
■ सेवाओं में व्यापार सुविधा के लिए डब्ल्यूटीओ में उठाई मांग

उन्होंने कहा कि यह समय है जबकि सेवाओं के व्यापार के लिए हमारे पास वैश्विक ढांचा होना चाहिए। हम सक्रिय तौर पर अपनास प्रस्ताव डब्ल्यूटीओ में आगे बढ़ाएंगे। सेवाओं में व्यापार सुगमता करार का मकसद पेशेवरों की आवाजाही के नियमों में ढील और लेनदेन की लागत को कम करने के लिए अन्य कदम उठाने से है।

भारत डब्ल्यूटीओ में इस करार को लेकर दबाव बना रहा है। देश की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का हिस्सा 60 फीसद है। यह क्षेत्र कुल रोजगार का 28 फीसद प्रदान करता है। सीतारमण ने कहा कि भारत चाहता है कि सभी सदस्य देश दिसम्बर में अर्जेंटीना में डब्ल्यूटीओ की मंत्री स्तरीय बैठक से पहले इस प्रस्ताव का अध्ययन करें। ■ भाषा

मुंजाल ने किया 100 करोड़ का निवेश

नई दिल्ली। हीरो एंटरप्राइज के अध्यक्ष सुनील कांत मुंजाल ने दूरदराज के क्षेत्रों में आम लोगों के जीवन में बदलाव की दिशा में काम करने वाली छोटी कंपनियों को वित्त उपलब्ध कराने वाली कंपनी आविष्कार के नए फंड 'आविष्कार भारत फंड' में 100 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की।

माइंडमाइन समिट में मुंजाल ने कहा कि यह निवेश रोजगार, शिक्षा एवं कौशल, पर्यावरण, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मौजूद प्रमुख चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से किया गया है और यह उनका व्यक्तिगत निवेश है। उन्होंने कहा कि देश को विकसित बनाने के लिए गांव और वंचित नागरिकों को न केवल परोपकार के जरिए बल्कि वास्तविक अवसरों के जरिए आर्थिक विकास का हिस्सा बनाना होगा। ■ वार्ता